



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

प्रत्यक्ष कर संहिता बनाम आयकर अधिनियम, 1961 की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा धमतरी जिला छ. ग.के विशेष संदर्भ में।

शोधार्थी।

केननकांता पटेल।

शोध निदेशक

डॉ काजोल दत्ता

सार:

कर भारत सरकार के राजस्व का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। वर्तमान में दो प्रमुख प्रकार के कर हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हैं। कराधान संरचना को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कानून हैं, विशेष रूप से प्रत्यक्ष कर, लेकिन ये कई कारणों से अप्रभावी रहे हैं जैसे जटिल अनुपालन, कर की बहुलता, दी गई उच्च छूट, जटिल प्रारूपण और कर कैस्केडिंग और टैक्स चोरी सहित विशिष्ट कर समस्याएं। इन समस्याओं की तह तक जाने के लिए, सरकार ने प्रत्यक्ष कर संहिता के रूप में एक नई पहल तैयार की है। कोड में आयकर अधिनियम, 1961 और संपत्ति कर, 1957 सहित सभी मौजूदा कानूनों को सरल और समेकित करने का प्रस्ताव है। हालांकि इस मामले पर 2010 से विचार-विमर्श हो रहा है, लेकिन इसे आज तक लागू नहीं किया गया है। यह पत्र कोड बनाने के मुख्य कारणों की पहचान करने का प्रस्ताव करता है और यह भी कि इसे अब तक क्यों निष्पादित नहीं किया गया है। साथ ही, कर संरचना न केवल एक इकाई को प्रभावित करती है, बल्कि सभी आर्थिक श्रेणियों को प्रभावित करती है, जिसमें व्यक्ति, निगम और अर्थव्यवस्था शामिल हैं, इस प्रकार उन पर कोड के प्रभाव को समझना कोड का मसौदा तैयार करने में सहायता कर सकता है। लेखक उन प्रमुख संरचनात्मक कमजोरियों की ओर भी इशारा करता है, जिनका कार्यान्वयन भाग को सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि काला धन, कर चोरी देश और देश की आबादी की तुलना में करदाताओं की न्यूनतम संख्या। एस्टोनिया देश के एक अध्ययन को ध्यान में रखा गया है क्योंकि इसे कर प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, 2022 में शीर्ष में से एक स्थान दिया गया है। पत्र कुछ प्रावधानों का भी सुझाव देता है जिन्हें कोड में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि सरकार 2023 के बजट सत्र में नया प्रत्यक्ष कर कोड पेश करने पर विचार कर रही थी जिसे 2024-25 में लागू किया जा रहा है।

कुंजी शब्द:

प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर संहिता, आयकर अधिनियम, 1961

परिचय:

नई प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) का उद्देश्य भारतीय कर संरचना को सरल और समझने में आसान बनाना है। आयकर अधिनियम, 1961 एक कठिन संरचना, कई संशोधनों, लगातार नीतिगत बदलावों और पहले से ही समझ से बाहर प्रावधानों की अलग-अलग व्याख्या करने वाले कई निर्णयों के कारण बहुत जटिल और आम आदमी के लिए समझने में लगभग असंभव हो गया है। इस जटिलता ने न केवल औसत करदाता के लिए अनुपालन की लागत बढ़ा दी है, बल्कि सरकार के लिए कर एकत्र करना भी महंगा बना दिया है। आयकर अधिनियम, 1961 के प्रतिस्थापन के लिए, नई प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) जो पूरी तरह से नई है, करदाताओं को मध्यम राहत देती है, अनावश्यक छूट को कम करती है और संग्रह में सुधार के लिए अनुपालन में सुधार करती है।

नई प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) की मदद से करदाता बिना किसी कर सलाहकार की मदद के खुद आयकर रिटर्न (आईटीआर) की गणना और फाइल कर सकते हैं। भारत के आयकर विभाग ने प्रत्यक्ष कर के लिए नया प्रस्ताव भारत सरकार के सामने रखा है और सरकार ने एकदम नए प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) कानून का मसौदा पेश किया है, जो पांच दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा, इसे प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) के नाम से जाना जाता है। नई प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) का उद्देश्य भारत में मौजूदा कर ढांचे को सरल और समझने में आसान बनाना है। हर साल वित्तीय बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कर दरों का विवरण रहा है। हालांकि, नई प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) की शुरुआत के साथ कर दरें हर साल संसद में पेश किए जाने वाले वित्तीय बजट का हिस्सा नहीं होंगी।

नया प्रत्यक्ष कर (डीटीसी) न केवल व्यक्तिगत करदाताओं, बल्कि कॉर्पोरेट घरानों और विदेशी निवासियों के लिए मौजूदा कर प्रस्तावों को पूरी तरह से बदल देगा। इसे अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में प्रचलित कर कानून से प्रेरणा लेकर तैयार किया गया है। भारत अपने प्रत्यक्ष कर कानूनों, मुख्य रूप से अपने आयकर अधिनियम, 1961 को आधुनिक बनाना चाहता है जो लगभग 50 वर्ष से अधिक पुराना है। सरकार को एक ऐसी अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप एक आधुनिक कर संहिता की आवश्यकता है जो अब एशिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नए प्रत्यक्ष कर (डीटीसी) से कर आधार का विस्तार होने, अनावश्यक छूट समाप्त होने और कर दरों में नरमी आने की उम्मीद है। इस पेपर का उद्देश्य और लक्ष्य आयकर अधिनियम, 1961 पर नए प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) के प्रभाव को जानना है।

भारत में प्रत्यक्ष कर संहिता की पृष्ठभूमि और आवश्यकता

कई अन्य आधुनिक देशों की तरह भारत में भी एक अच्छी तरह से विकसित और विविधतापूर्ण कर ढांचा है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें एक दूसरे को कर लगाने का अधिकार साझा करती हैं। व्यावसायिक कर और कृषि आयकर के अपवाद के साथ प्रत्यक्ष कर ज्यादातर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, जबकि अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार और राज्य दोनों द्वारा लगाए जा सकते हैं।

भारत के अच्छी तरह से संरचित करों के बावजूद, प्रणाली में कुछ गंभीर खामियां हैं, जिनमें शामिल हैं:-

1. जटिल अनुपालन: कई कानूनों, जैसे कि आयकर अधिनियम 1961, आदि के तहत जो अनुपालन पूरा किया जाना चाहिए, वह करदाताओं के लिए कर भुगतान को एक बड़ा बोझ बना देता है।

2. कर का कैस्केडिंग: कैस्केड टैक्स या कैस्केडिंग टैक्स एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करता है, जो कच्चे माल से उपभोक्ता खरीद तक आपूर्ति श्रृंखला में प्रत्येक क्रमिक चरण में उत्पादों पर बिक्री कर लगाता है। आपूर्ति श्रृंखला में प्रत्येक खरीददार अपनी लागत के आधार पर कीमत चुकाता है, जिसमें पिछला कर या लगाए गए कर शामिल होते हैं। यदि सरकार उत्पादित और आपूर्ति की गई सभी वस्तुओं पर कैस्केड टैक्स के रूप में 1% कर लगाती है, तो उदाहरण के लिए, पत्थर के एक स्लैब की कीमत 100 रुपये है, लेकिन इसे एक कलाकार को 101

रुपये में बेचा जाता है। कलाकार पत्थर के स्लैब से एक उत्पाद तैयार करता है और 100 रुपये का और लाभ कमाने को तैयार है, इसलिए कलाकार डीलर को उत्पाद 203 रुपये (101 रुपये + 100 रुपये का वांछित लाभ) + इस कुल राशि का 1% की कीमत पर बेचेगा। मान लीजिए कला डीलर 500 रुपये का लाभ कमाना चाहता है, इसलिए जिस अंतिम मूल्य पर उत्पाद बेचा जाता है, वह 811 रुपये होता है। इस प्रकार, समस्या यह है कि सरकार 1% लाभ कमाने के कर के बजाय कुल लगभग 2% कर अर्जित होता है जो दोगुना है। इस समस्या का समाधान प्रत्यक्ष कर संहिता द्वारा किया जा सकता है।

3. कई उत्पादों या उत्पादकों की श्रेणियों को दी गई छूट या रियायतें: भारत में कृषि राजस्व कराधान से मुक्त है। सातवें संशोधन की अनुसूची VII में राज्य सूची राज्यों को कृषि राजस्व पर कर लगाने की क्षमता प्रदान करती है। करदाता कृषि आय के बहाने कई तरह की आय का दावा करना चाहते हैं।

4. करों की बहुलता: करों की बहुलता के कारण भारत के नागरिकों में कर ढांचे को लेकर नाखुशी है। संघ सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों द्वारा लगाए गए करों के कारण करदाता को मुश्किलों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। उसे कई अधिकारियों से संपर्क करना पड़ता है और उनमें से प्रत्येक के लिए अलग-अलग रिकॉर्ड बनाए रखने पड़ते हैं। एक आदर्श कर प्रणाली को एडम स्मिथ के कराधान के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, लेकिन अप्रत्यक्ष करों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण, कर प्रणाली असमानता, प्रतिगामी, अलाभकारी, मुद्रास्फीति आदि जैसी समस्याओं से ग्रस्त है। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले करों में कस्टम टैक्स, उत्पाद शुल्क, सेवा कर और सबसे महत्वपूर्ण आयकर शामिल हैं। राज्य सरकार केंद्रीय बिक्री कर, वैट, स्टॉप ड्यूटी जैसे कर लगाती है, इस प्रकार एक सरलीकृत कर संरचना की आवश्यकता होती है क्योंकि जटिलता व्यक्तियों को करों का भुगतान करने से हतोत्साहित करती है।

5. जटिल प्रारूपण: इसके अनुभागों और आवश्यकताओं की जटिल भाषा के परिणामस्वरूप, 1961 का आयकर अधिनियम समझना और समझना मुश्किल है, जो कानून के गैर-अनुपालन का औचित्य प्रदान करता है। 12 अगस्त 2009 को मौजूदा कानून को कारगर बनाने और संयोजित करने के लिए, भारत सरकार ने सार्वजनिक टिप्पणी के लिए डीटीसी का पहला मसौदा विधेयक जारी किया, साथ ही एक चर्चा पत्र (डीटीसी 2009) भी जारी किया। 2010 में, विभिन्न हितधारकों की टिप्पणियों के जवाब में एक संशोधित चर्चा पत्र (आरडीपी) जारी किया गया था। डीटीसी 2010 को अगस्त 2010 में भारतीय संसद में पेश किया गया था, और इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से वित्त पर एक स्थायी समिति (एससीएफ) का गठन किया गया था। 9 मार्च 2012 को, वित्त पर स्थायी समिति ने विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद भारतीय संसद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति के निष्कर्षों के बाद, कोड का एक अद्यतन संस्करण बाद में 2014 में तैयार किया गया था। हालांकि, सरकार में बदलाव के कारण कानून समाप्त हो गया। 2014 के आम चुनाव के बाद से ही इस पर चर्चा चल रही है। 2017 में एक नया विशेषज्ञ समूह बनाया गया था; इसने 2019 में वित्त मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी; और सरकार जल्द से जल्द एक नया प्रत्यक्ष कर कोड लागू करने की योजना बना रही है। जो वित्त मंत्री द्वारा अगस्त 2024 में घोषणा किया है कि 2024-25 में लागू हो जाएगा।

नए प्रत्यक्ष कर कोड से क्या उम्मीद की जा सकती है?

भारत सरकार ने प्रत्यक्ष कर व्यवस्था में कई बदलावों के साथ बजट 2023 पेश किया और वित्तीय वर्ष 2023 के बजट सत्र के दौरान एक नया प्रत्यक्ष कर कोड प्रकाशित करने की भी उम्मीद थी, जो 2017 में स्थापित टास्क फोर्स की सिफारिशों पर आधारित था और जो 2019 में अपनी रिपोर्ट पेश की, हालांकि इसकी घोषणा नहीं की गई।

बजट 2023 में किए गए महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कर परिवर्तन इस प्रकार हैं:

1. दआयकर अधिनियम 1961 की धारा 87ए में बदलाव किया गया है ताकि नई कर प्रणाली चुनने वाले लोग अपनी कुल आय के 7 लाख रुपये तक अधिक पर छूट पा सकें। यह 5 लाख रुपये से वृद्धि है। नई कर प्रणाली के तहत, यदि आपकी कर योग्य आय 7 लाख रुपये से कम है, तो आपको कोई आयकर नहीं देना होगा।

2. नई कर प्रणाली के तहत मूल छूट सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़कर 3 लाख रुपये हो गई है। नई आयकर प्रणाली के तहत 3 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना होगा।

3. मानक कटौती अब वैकल्पिक कर व्यवस्था का भी हिस्सा है। सरलीकृत कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी लोगों को 50,000 रुपये की मानक कटौती मिल सकती है। नई कर प्रणाली के तहत, पेंशनभोगी भी 15,000 रुपये की मानक कटौती लेने का विकल्प चुन सकते हैं।

4. 3,00,000 रुपये तक: शून्य 300,000 से 6,00,000 रुपये: 3,00,000 रुपये से अधिक की आय पर 5% 6,00,000 से 9,00,000 रुपये: 6,00,000 रुपये से अधिक की आय पर 15,000 रुपये + 10% 9,00,000 से 12,00,000 रुपये: 9,00,000 रुपये से अधिक की आय पर 45,000 रुपये + 15% 12,00,000 से 15,00,000 रुपये 15,00,000: 12,00,000 रुपये से अधिक की आय पर 90,000 + 20% 15,00,000 रुपये से अधिक: 150,000 रुपये + 15,00,000 रुपये से अधिक की आय पर 30% हालांकि, इस कोड के भविष्य के कार्यान्वयन के लिए समय की आवश्यकता और सिफारिशों के आधार पर नए प्रत्यक्ष कर संहिता से कुछ पहलुओं की उम्मीद की जा सकती है, और वे डीटीसी को देश के कर सुधार इतिहास में एक गेम-चेंजर बना सकते हैं।

सबसे पहले, यह अनुमान लगाया गया है कि डीटीसी अधिनियम की तुलना में छोटा होगा, जिसमें 298 भाग शामिल हैं, और स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा के उपयोग के माध्यम से "प्रावधानों" और "स्पष्टीकरणों" के जटिल जाल को हटाकर वर्तमान कानून को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा, समय के साथ कर राजस्व की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है, जिससे विभाग को अनुपालन लागतों पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लागतों को कम करने के लिए, एक ऐसी वास्तुकला के निर्माण में सहायता करना आवश्यक है जिसमें करदाता कानून के साथ स्वैच्छिक अनुपालन का समर्थन करते हैं। यह कानून की सरलता और अर्थ की स्पष्टता को बनाए रखने के माध्यम से पूरा किया जाना है।

नया डीटीसी काफी सीधा है, इसमें कम धाराएँ हैं, और यह 1961 के आयकर अधिनियम के कई अजीबोगरीब हिस्सों को भी बदल देता है। चूंकि स्टार्ट-अप आर्थिक विकास के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि उनके लिए कई प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे, क्योंकि प्रोत्साहनों के माध्यम से उनका प्रचार अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित कर सकता है। चूंकि "एंजल टैक्स" ने करदाताओं के लिए अनावश्यक कठिनाई पैदा की है, इसलिए एक क्रांतिकारी बदलाव यह होगा कि इसे खत्म कर दिया जाए। यह पूरी तरह से लागू है।

वास्तव में, 2019 वित्त अधिनियम और उसके कार्यान्वयन के बाद कई उपाय पहले ही लागू किए जा चुके हैं। तीसरा, यह अनुमान है कि व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट करदाताओं से निपटने वाली कर प्रक्रियाओं के लिए मूल्यांकन इकाई लागू की जाएगी, जो कर अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच सभी बातचीत डिजिटल रूप से की जाएगी। इसके अलावा, सभी डिजिटल संचार में एक अद्वितीय दस्तावेज़ पहचान संख्या होगी। इसके अलावा, डीटीसी की तरह कर प्रणाली के सरलीकरण की उम्मीद की जा सकती है जिसके तहत सभी कर दरों को अनुसूचियों में निर्धारित करने का प्रस्ताव है, जो हर प्रासंगिक वर्ष के वित्त अधिनियम की जरूरतों को पूरा करता है। इसके अलावा, किसी नए कर कानून की दर अनुसूचियों में किसी भी प्रस्तावित संशोधन को कार्यान्वयन से पहले मंजूरी के लिए संशोधन विधेयक के रूप में विधायिका को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उद्यमों के लिए मूल निगम कर

की दर घटाकर 25% कर दी जाएगी, जो विशेष रूप से विदेशी कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण कमी होगी। इससे भारत में अधिक अंतर्राष्ट्रीय फर्म और नकदी आकर्षित होगी, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन यह उन भारतीय उद्यमों के लिए उचित खेल का मैदान प्रदान नहीं करेगा जो सख्त अनुपालन मानकों के अधीन हैं।

इसके अलावा, नया कर कानून एक अतिरिक्त लाभप्रद प्रावधान प्रदान कर सकता है जो निगमों को लाभांश वितरण कर का भुगतान करने से छूट देता है, जो 15% प्लस 12% अधिभार प्लस 3% उपकर है, और परिणामस्वरूप 20.35% है। ऐसी संभावना है कि केवल शेयरधारकों पर लाभांश पर कर लगाया जाएगा। यह निगमों को ऐतिहासिक मानदंडों की तुलना में उच्च दर पर लाभांश जारी करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। इसके अलावा, इसे अपडेट करना सरल होना चाहिए, क्योंकि नए प्रत्यक्ष कर कोड को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि कानून मूल और सामान्य सिद्धांतों द्वारा व्यक्त किया जाए, यथासंभव अधिकतम सीमा तक, और विशिष्ट मामले को नियमों/अनुसूचियों में समाहित किया जाए। इसके अलावा, विचारों में से एक 'मध्यस्थता' शब्द को अपनाना है। यदि इसे अपनाया जाता है, तो यह नई धारणा भारतीय कानून में पहली बार पेश की जाएगी। करदाता को मसौदा निर्णय प्राप्त करने के बाद आयुक्तों के कॉलेजियम के समक्ष बातचीत के जरिए समाधान चुनने की अनुमति होगी। दोनों पक्षों पर, मध्यस्थ चर्चाओं में सहायता करेंगे। यह दृष्टिकोण इस विश्वास के साथ सुझाया गया है कि कर मुकदमेबाजी में काफी कमी आएगी। इस तंत्र की स्थापना के साथ, यह संभव है कि निपटान आयोग प्रक्रिया डीटीसी को चुपचाप छोड़ देगी। एक अलग "मुकदमेबाजी प्रबंधन इकाई" का निर्माण एक अतिरिक्त उल्लेखनीय संशोधन है। यह टीम संपूर्ण कर मुकदमेबाजी प्रक्रिया की देखरेख करेगी, जिसमें कर निर्धारण से लेकर कर चोरी तक शामिल है। क्या मामलों में बचाव रणनीति विकसित करने के लिए अपील की आवश्यकता है।

प्रस्तावित दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि कर अधिकारी जो मूल्यांकन आदेश जारी करता है, वह अब अपील दायर नहीं करेगा। सरकार ने मुकदमेबाजी की मात्रा को कम करने के लिए पिछले वर्ष अपेक्षाकृत प्रभावी कदम उठाए हैं। एक विशिष्ट कर सीमा तक अपील दायर करने पर रोक लगाने वाले प्रशासनिक आदेश जारी किए गए हैं, और निर्धारित स्तर से नीचे कर प्रभाव वाली लंबित अपीलों को हटा दिया गया है। 2019 में अपनी रिपोर्ट पेश की, हालांकि इसकी घोषणा नहीं की गई।

बजट 2023 में किए गए महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कर परिवर्तन इस प्रकार हैं:

1. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 87ए में बदलाव किया गया है ताकि नई कर प्रणाली चुनने वाले लोग अपनी कुल आय के 7 लाख रुपये तक अधिक पर छूट पा सकें। यह 5 लाख रुपये से वृद्धि है। नई कर प्रणाली के तहत, यदि आपकी कर योग्य आय 7 लाख रुपये से कम है, तो आपको कोई आयकर नहीं देना होगा।

2. नई कर प्रणाली के तहत मूल छूट सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़कर 3 लाख रुपये हो गई है। नई आयकर प्रणाली के तहत 3 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना होगा।

3. मानक कटौती अब वैकल्पिक कर व्यवस्था का भी हिस्सा है। सरलीकृत कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी लोगों को 50,000 रुपये की मानक कटौती मिल सकती है। नई कर प्रणाली के तहत, पेंशनभोगी भी 15,000 रुपये की मानक कटौती लेने का विकल्प चुन सकते हैं।

4. 3,00,000 रुपये तक: शून्य 300,000 से 6,00,000 रुपये: 3,00,000 रुपये से अधिक की आय पर 5% 6,00,000 से 9,00,000 रुपये: 6,00,000 रुपये से अधिक की आय पर 15,000 रुपये + 10% 9,00,000 से 12,00,000 रुपये: 9,00,000 रुपये से अधिक की आय पर 45,000 रुपये + 15% 12,00,000 से 15,000 रुपये 15,00,000: 12,00,000 रुपये से अधिक की आय पर 90,000 + 20% 15,00,000 रुपये से अधिक: 150,000 रुपये + 15,00,000 रुपये से अधिक की आय पर 30% हालांकि, इस कोड के भविष्य के कार्यान्वयन के लिए समय की आवश्यकता और सिफारिशों के आधार पर नए प्रत्यक्ष कर संहिता से कुछ पहलुओं की उम्मीद की जा सकती है,

और वे डीटीसी को देश के कर सुधार इतिहास में एक गेम-चेंजर बना सकते हैं।

सबसे पहले, यह अनुमान लगाया गया है कि डीटीसी अधिनियम की तुलना में छोटा होगा, जिसमें 298 भाग शामिल हैं, और स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा के उपयोग के माध्यम से "प्रावधानों" और "स्पष्टीकरणों" के जटिल जाल को हटाकर वर्तमान कानून को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा, समय के साथ कर राजस्व की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है, जिससे विभाग को अनुपालन लागतों पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लागतों को कम करने के लिए, एक ऐसी वास्तुकला के निर्माण में सहायता करना आवश्यक है जिसमें करदाता कानून के साथ स्वैच्छिक अनुपालन का समर्थन करते हैं। यह कानून की सरलता और अर्थ की स्पष्टता को बनाए रखने के माध्यम से पूरा किया जाना है। नया डीटीसी काफी सीधा है, इसमें कम धाराएँ हैं, और यह 1961 के आयकर अधिनियम के कई अजीबोगरीब हिस्सों को भी बदल देता है। चूंकि स्टार्ट-अप आर्थिक विकास के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि उनके लिए कई प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे, क्योंकि प्रोत्साहनों के माध्यम से उनका प्रचार अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित कर सकता है।

प्रत्यक्ष कर संहिता की प्रमुख संरचनात्मक कमज़ोरियाँ :-

यद्यपि भारत सरकार ने इस अभिनव कानून को लागू करके एक ठोस शुरुआत की है, लेकिन करों के क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने कई गंभीर चुनौतियाँ अभी भी अनसुलझी हैं। सबसे बड़ी चुनौती काला धन है, जो अवैध रूप से कमाया गया धन है, या जिस पर आवश्यक कर का भुगतान नहीं किया जाता है। भले ही इसमें गैरकानूनी रणनीति शामिल हो, कर चोरी प्रतिबंधात्मक कर व्यवस्थाओं में या ऐसी स्थितियों में जीवित रहने की रणनीति है, जहाँ व्यावसायिक गतिविधि की वैध अभिव्यक्ति कानूनों के जाल द्वारा अनावश्यक रूप से बोझिल हो जाती है। काली अर्थव्यवस्था और काला धन एक साथ चलते हैं और इन्हें समानांतर अर्थव्यवस्था, छाया अर्थव्यवस्था या भूमिगत अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है।

नीति निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती भारत में समानांतर अर्थव्यवस्था का लगातार बढ़ता आकार है। दिसंबर 2012 में ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया के शीर्ष दस विकासशील देशों में से एक है, जहाँ 2010 में 1.6 बिलियन डॉलर (8,720 करोड़ रुपये) का काला धन बाहर गया। कुल काला धन बाहर जाने की राशि 232 बिलियन डॉलर थी, मुख्य रूप से रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और रियल एस्टेट लेनदेन के माध्यम से। उसी समय सीमा के दौरान भारतीयों के स्वामित्व वाली अवैध संपत्तियों का अनुमानित कुल मूल्य 487 बिलियन डॉलर है।

भारत में काले धन के प्रमुख कारण हैं:-

- आर्थिक संचालन पर सरकारी सीमाएँ।
- सरकारी धन में वृद्धिखर्च और पारदर्शिता की कमी।
- राजनीतिक वित्तपोषण।
- भारत में कराधान संरचना।
- कर से बचने के खिलाफ़ कमज़ोर प्रतिरोध।
- निम्न नैतिक मानक।
- मुद्रास्फीति।
- काले धन की सामाजिक स्वीकार्यता, आदि।

कराधान से काला धन पैदा हो सकता है, क्योंकि उच्च कर दरें कर चोरी को भी बढ़ाती हैं। इसलिए, समय की मांग है कि देश की कर प्रणाली को इस तरह से डिज़ाइन किया जाए जो इन समस्याओं को ध्यान में रखे।

भारत से कर पनाहगाहों में नकदी का बहिर्वाह एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे भारतीय नीति निर्माताओं को संबोधित करना चाहिए। भूमिगत अर्थव्यवस्था की तरह, भारत से पूंजी पलायन के अलग-अलग अनुमान हैं। टैक्स हेवन एक ऐसा देश है, जिसमें विदेशियों या विदेशी कंपनियों के कराधान का वास्तविक गृह देश में कर के बोझ को कम करने के लिए लाभकारी शर्तों पर शोषण किया जाता है। "टैक्स हेवन" शब्द की कोई सटीक परिभाषा नहीं है। यह निर्धारित करने के लिए कोई पूर्ण मानदंड नहीं है कि कोई देश कर आश्रय है या नहीं। अनिवार्य रूप से, कोई भी देश कर-हेवन हो सकता है, बशर्ते कि परिस्थितियाँ किसी व्यक्ति या व्यवसाय के लिए अनुकूल हों। ऐसे फंड न तो कर-हेवन में योगदान किए जाते हैं और न ही गृह देश के करों में, बल्कि उन क्षेत्रों में कटौती के रूप में दावा किए जाते हैं जो कर-हेवन नहीं हैं (कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस, 2022)। शोध बताते हैं कि दुनिया भर की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ कर-हेवन प्रथाओं के 98 प्रतिशत में योगदान देती हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफे का 40 प्रतिशत कर-हेवन में निवेश किया जाता है, जिससे वैश्विक स्तर पर सालाना 200 बिलियन अमरीकी डॉलर का नुकसान होता है।

एक बार जब यह भारी मात्रा में गंदा पैसा और संपत्ति भारत में वापस आ जाती है, तो चौबीस घंटे के भीतर पूरा विदेशी ऋण चुकाया जा सकता है। अपने कुल विदेशी ऋण का भुगतान करने के बाद, हमारे पास एक अधिशेष राशि होगी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय ऋण से 12 गुना अधिक होगी। यदि इस अतिरिक्त राशि को ब्याज उत्पन्न करने के लिए निवेश किया जाता है, तो अर्जित धन संघीय सरकार के वार्षिक बजट से अधिक होगा। इसलिए यदि सभी कर समाप्त कर दिए जाएं तो भी राष्ट्र जीवित रह सकता है। इसके अलावा, भारत की वर्तमान जनसंख्या 2021 में अनुमानित 1380 मिलियन है, लेकिन 31 जुलाई तक दाखिल किए गए कुल आईटीआर में केवल करदाताओं की ही गिनती की जाती है। AY 22-23 के लिए 2022 तक कुल कर लगभग 5.83 करोड़ है, इसलिए जब तक इस बड़े हिस्से पर कर नहीं लगाया जाता, तब तक यह संभव है कि कोई भी कराधान योजना इच्छित परिणाम प्रदान न करे।

भारत में करदाताओं की छोटी संख्या के अलावा, कर दाखिल करने वालों में से अधिकांश का भुगतान बहुत कम किया जाता है और उनका अवमूल्यन किया जाता है, जो अपने आप में एक मुद्दा है। भारत में, आयकर का भुगतान वित्तीय और वाणिज्यिक विचारों के बाहर एक पवित्र कार्य के रूप में नहीं देखा जाता है। एक व्यक्ति जो करों का भुगतान करता है, उसके पास कोई विशेषाधिकार प्राप्त सामाजिक स्थिति नहीं होती है। इसके बजाय, एक व्यक्ति जो अपने कर रिटर्न में हेरफेर करता है, वह उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा का आनंद लेता है। यह मूल्य प्रणाली न केवल पिछड़ी है, बल्कि समाज के लिए भी खतरनाक है।

समस्या का विवरण:

“आयकर अधिनियम, 1961 पर नए प्रत्यक्ष कर कोड (डीटीसी) का प्रभाव”

अध्ययन के उद्देश्य:

1. यह पता लगाना कि करदाता कर सलाहकार की मदद के बिना आयकर रिटर्न (आईटीआर) की गणना और फाइल कर सकते हैं।
2. मध्यम राहत के लिए नए प्रत्यक्ष कर कोड (डीटीसी) की मदद का पता लगाना।
3. यह जानना कि नए प्रत्यक्ष कर कोड (डीटीसी) से अनावश्यक छूट कम हो जाएगी।
4. यह जानना कि ईईटी मॉडल भविष्य में अधिक कर एकत्र करेगा।

संबंधित साहित्य की समीक्षा:

- महफूज अहमद (1968) ने अपने लेख "भारत में कर संग्रह की लागत" में निष्कर्ष निकाला कि यदि कर संग्रह की लागत विभिन्न करों के बीच चयन करने का एकमात्र मानदंड है, तो प्रमुख केंद्रीय करों की तुलना में सीमा शुल्क और आयकर तथा उत्पाद शुल्क आयकर से बेहतर हैं। प्रत्यक्ष करों का संग्रह अप्रत्यक्ष करों की तुलना में अधिक महंगा है।
- दास-गुप्ता, अरिंदम, राधिका लाहिडी और दिलीप मुखर्जी (1995) ने अपने शोध पत्र "भारत में आयकर अनुपालन: एक अनुभवजन्य विश्लेषण" में पाया कि कर राजस्व संग्रह और कर अनुपालन कर संरचना (सीमांत कर दरें और छूट सीमा) से काफी प्रभावित थे।
- निशांत गेज और कटदारे (2015) ने अपने लेख, "भारतीय कर संरचना - एक विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य" में चार वर्षों की अवधि में विभिन्न प्रकार के करों से एकत्रित कर राजस्व की मात्रा की पहचान की, अप्रत्यक्ष कर संग्रह की राशि प्रत्यक्ष करों से एकत्रित राशि से लगभग दोगुनी थी।
- प्रमोद कुमार पांडे (2017) ने अपने लेख, "भारतीय कराधान प्रणाली का इसके आर्थिक विकास पर प्रभाव" में पहचाना कि भारत के आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का प्रभाव मौजूद है। शोध पद्धति: इस अध्ययन के प्रमुख शोध उद्देश्य यह पता लगाना है कि भारत के आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का प्रभाव क्या है।
- प्रेस्ट (1962) ने अपने अध्ययन में समीक्षा की कि शोध की अवधि के दौरान यू.के. (यूनाइटेड किंगडम) में व्यक्तिगत आय में वृद्धि हुई है, लेकिन आयकर संग्रह में कोई वृद्धि नहीं हुई है। कर कानून के तहत भत्ते और छूट के कारण यह स्थिति मौजूद है। इसका मतलब है कि सरकार को व्यक्तिगत आयकर ढांचे में कुछ बदलाव करके अधिक आयकर एकत्र करने के लिए कुछ उपचारात्मक कदम उठाने होंगे। उन्होंने 1947-1961 की अवधि के दौरान यू.के. (यूनाइटेड किंगडम) में अपना अध्ययन पूरा किया।
- ब्रिस्टो (1968) उन्होंने देश में आर्थिक स्थिरीकरण के लिए 1955 से 1965 तक ब्रिटेन में अध्ययन किया। उन्होंने समीक्षा की कि जब सरकार ने प्रत्यक्ष कर की दरें कम कीं तो कर संग्रह में वृद्धि हुई। प्रत्यक्ष कर दरों में वृद्धि के मामले में सरकार द्वारा कर संग्रह में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष कर संरचना देश में करों के संग्रह को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।
- सिंह और शर्मा (2006) ने भारत और संघीय अमेरिका में ईईटी प्रणाली (छूट-छूट-कर) पर अध्ययन का विश्लेषण किया। अध्ययन दोनों देशों के ईईई (छूट-छूट-छूट) के शुद्ध वर्तमान मूल्य के आधार पर किया गया था। अध्ययन ने मूल्यांकन किया कि भारतीय करदाताओं की क्रय शक्ति उनके राजस्व से अधिक थी। अध्ययन ने सुझाव दिया कि दुनिया के अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय कर ढांचे की कमजोरियों को जल्द से जल्द सुधारना चाहिए।
- अनिल कुमार जैन और पारुल जैन (2007): उन्होंने अध्ययन अवधि के दौरान भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के तहत बचत के कर उपचार का अध्ययन किया। उन्होंने यह भी विश्लेषण

किया और अध्ययन किया कि ईईईई (छूट-छूट-छूट) से ईईटी (छूट-छूट-कर योग्य) में बदलाव का प्रभाव भारत में वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में वांछनीय होगा। अध्ययन में कहा गया है कि इस अस्थायी बदलाव ने करदाताओं के मन में और उनके निवेश में भी अनिश्चितता पैदा कर दी है। यह माना गया कि कर कानून में बचतकर्ताओं के साथ-साथ निवेशकों के लिए कर प्रोत्साहन को अच्छी तरह से लक्षित किया जाना चाहिए। अध्ययन ने सुझाव दिया कि ईईटी प्रणाली में अचानक बदलाव से भारत के आयकर अधिनियम में अनिश्चितता और बढ़ जाएगी।

शोध पद्धति:

शोधकर्ता अध्ययन के प्रकार-

प्रस्तावित अध्ययन प्रकृति में वर्णनात्मक है। धमतरी के विभिन्न मूल्यांकनकर्ताओं से डेटा एकत्र करने के लिए एक क्षेत्र अध्ययन किया गया है।

शोधकर्ता साधन

अध्ययन के लिए मूल्यांकनकर्ताओं से प्राथमिक डेटा एकत्र करने के लिए प्रश्नावली का उपयोग एक उपकरण के रूप में किया जाता है।

अध्ययन की प्रकृति को देखते हुए, प्रश्नावली का ढांचा तैयार किया जा रहा है और इसमें मुख्य रूप से खुले और बंद दोनों तरह के प्रश्न होंगे। शोध कार्य के लिए परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए एक क्षेत्र अध्ययन किया जाता है।

शोधकर्ता नमूनाकरण योजना

शोध कार्य में धमतरी जिला के विभिन्न हिस्सों से डेटा एकत्र किया जाता है। अध्ययन के लिए नमूनाकरण की सुविधाजनक विधि का उपयोग करके धमतरी के मुख्य विकास खंड का चयन किया जाता है।

शोधकर्ता नमूना आकार

अध्ययन धमतरी जिला के विभिन्न मूल्यांकनकर्ताओं के बारे में है। धमतरी जिला में मूल्यांकनकर्ताओं की संख्या को देखते हुए, अध्ययन के लिए 400 मूल्यांकनकर्ताओं के नमूने के लिए एक सुविधाजनक नमूना लिया गया है। धमतरी जिला के प्रत्येक विकासखण्ड से आनुपातिक रूप से लिए गए हैं। शोधकर्ता डेटा संग्रह योजना प्राथमिक डेटा शोधकर्ता ने प्रश्नावली की मदद से धमतरी जिला के विभिन्न विकास खंड में स्थित विभिन्न करदाताओं से आवश्यक प्रत्यक्ष जानकारी एकत्र की है।

द्वितीयक डेटा शोधकर्ता ने संदर्भ पुस्तकों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, इंटरनेट और अन्य शोध स्रोतों जैसे प्रकाशित साहित्य से द्वितीयक जानकारी एकत्र की है।

अध्ययन की सीमाएँ

अध्ययन केवल धमतरी जिला के करदाताओं पर आधारित है। डेटा धमतरी जिला के केवल 400 करदाताओं से एकत्र किया गया है। डीटीसी के लिए व्यक्तिगत करदाताओं का दृष्टिकोण अलग हो सकता है। अध्ययन के लिए केवल व्यक्तिगत करदाताओं पर विचार किया जाता है। चूंकि नई प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) के लिए सरकारी नीति बदल सकती है।

आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या :-

वर्णनात्मक सांख्यिकी तालिका (1) उद्देश्य (1) का उपयोग करके डेटा संग्रह विश्लेषण

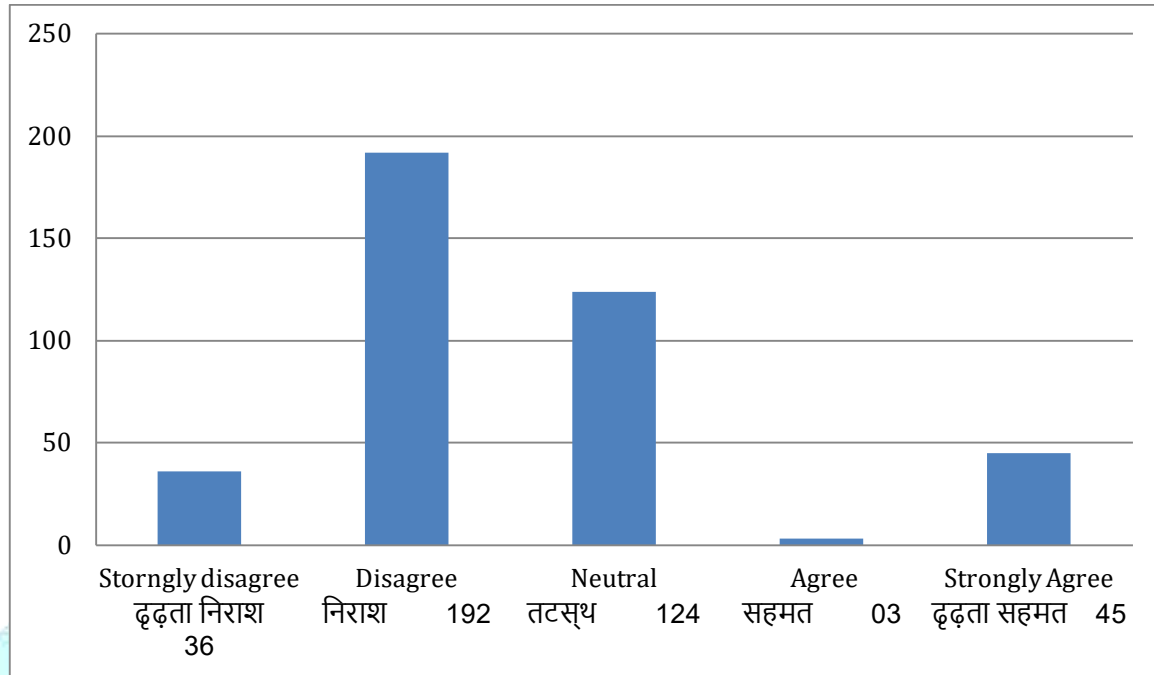
तालिका (1) उद्देश्य (1)

नया प्रत्यक्ष कर कोड करदाता कम्प्यूटर और कर परामर्श की मदद के बिना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं?

Opinion राय	frequency आवृत्ति	Percently प्रतिशत	Valid Percent वैध प्रतिशत	Cumulative Percent संचयी प्रतिशत
Strongly Disagree दृढ़ता निराश	36	9.0	9.0	9.0
Disagree निराश	192	48.0	48.0	57.0
Neutral तटस्थ	124	31.0	31.0	88.0
Agree सहमत	03	08	08	88.8
Strongly Agree दृढ़ता सहमत	45	11.3	11.3	100.0
Total कुल	400	100.00	100.00	-

(प्रश्नावली से संकलित)

नया प्रत्यक्ष कर कोड करदाता कम्प्यूटर और कर परामर्श की मद के बिना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते है?



(प्रश्नावली से संकलित)

आकृति 1.

नया प्रत्यक्ष कर कोड करदाता कम्प्यूटर और कर परामर्श के बिना दाखिल कर सकते है।

व्याख्या-

निम्नालिखित तालिका 01 और आकृति 01 से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नए प्रत्यक्ष कर कोड के संबंध में उत्तरदाताओं की सहमति से कर सलाहकार की सहायता के बिना कम्प्यूटर और आयकर रिटर्न दाखिल करने में मद मिलेगी।

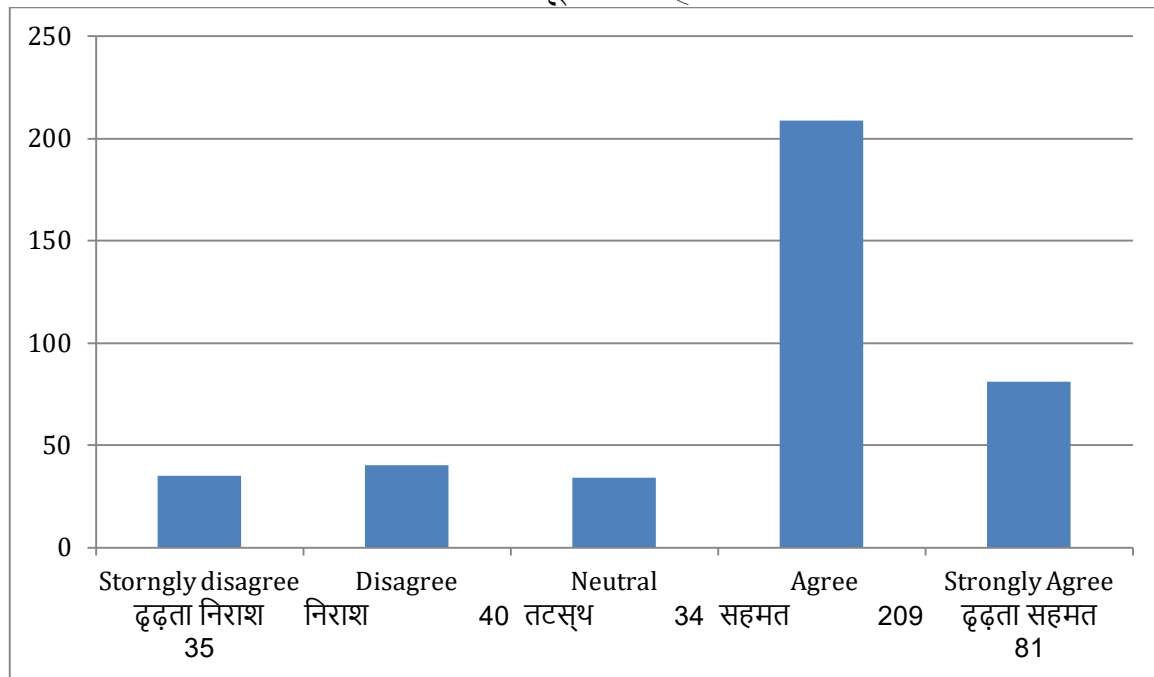
तालिका-2 (उद्देश्य 2)

नया प्रत्यक्ष कर कोड आपको मामूली राहत देकर मदद करेगा।

Opinion राय	frequency आवृत्ति	Percently प्रतिशत	Valid Percent वैध प्रतिशत	Cumulative Percent संचयी प्रतिशत
Strongly Disagree दृढता निराश	35	8.8	8.8	8.8
Disagree निराश	40	10.0	10.0	18.8
Neutral तटस्थ	34	8.5	8.5	27.3
Agree सहमत	209	52.3	52.4	79.7
Strongly Agree दृढता सहमत	81	20.3	20.3	100.00
कुल	399	99.8	100.00	-
अप्राप्त	1	3	-	-
कुल	400	100	-	-

(प्रश्नावली से संकलित)

नया कर कोड आपको मामूली राहत देकर मदद करेगा ।



(प्रश्नावली से संकलित)

आकृति 02 (नया कर कोड आपको मामूली राहत देकर मदद करेगा)

व्याख्या-

निम्न तालिका 02 और आंकड़ा इसलिए नए कर कोड के बारे में जवाब देने वालों की सहमति आपको संशोधित राहत के मदद करेगी। यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि यह राहत में अधिक मदद करेगा। केवल 19% उत्तरदाताओं का मानना है कि यह संशोधित राहत के लिए मदद नहीं करेगा। यह दर्शाया जा सकता है कि नया कर कोड सिस्टम में मदद करेगा।

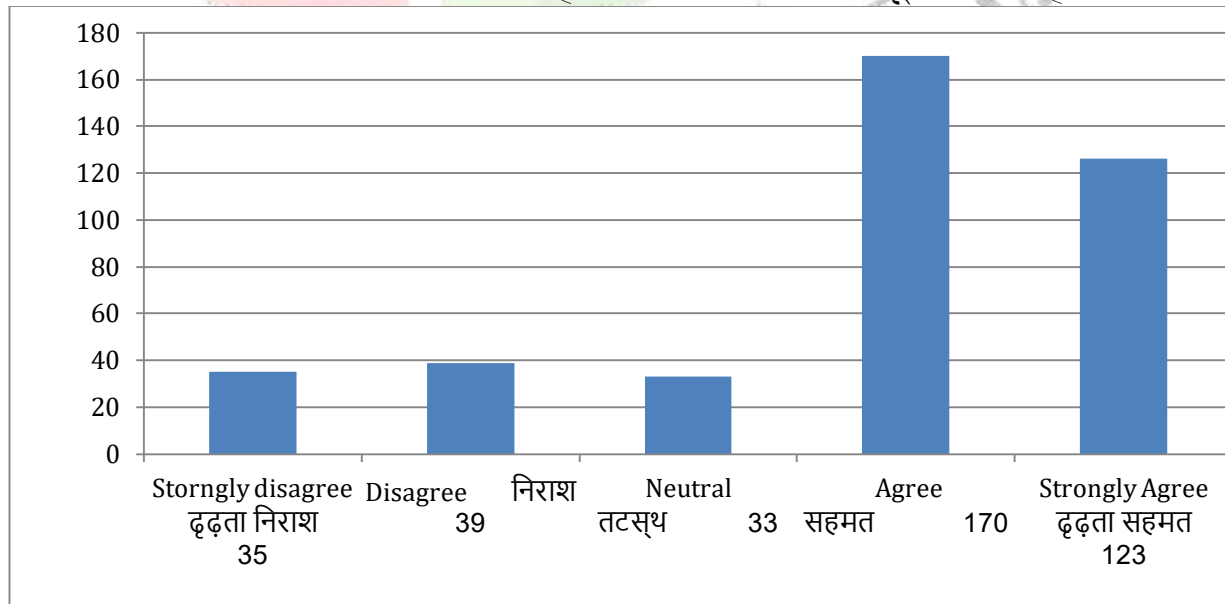
तालिका-3 (उद्देश्य 3)

नया प्रत्यक्ष कर संहिता (कोड) से अनावश्यक छूट कम हो जाएगी।

Opinion राय	frequency आवृत्ति	Percently प्रतिशत	Valid Percent वैध प्रतिशत	Cumulative Percent संचयी प्रतिशत
Strongly Disagree दृढ़ता निराश	35	8.8	8.8	8.8
Disagree निराश	39	9.8	9.8	18.5
Neutral तटस्थ	33	8.3	8.3	26.8
Agree सहमत	170	42.5	42.5	69.3
Strongly Agree दृढ़ता सहमत	123	30.8	30.8	100.00
Total कुल	400	100.00	100.00	-

(प्रश्नावली से संकलित)

नया प्रत्यक्ष कर संहिता से अनावश्यक छूट कम हो जायेगा।



(प्रश्नावली से संकलित)

आवृत्ति-3 नया प्रत्यक्ष कर संहिता से अनावश्यक छूट कम हो जाएगा।

व्याख्या-

तालिका 03 और चित्र 03 से यह दर्शाया गया है कि नए कर कोड के बारे में उत्तरदाताओं की सहमति अनावश्यक छूट को कम करेगी इसका मतलब है कि करदाताओं ने अनावश्यक छूट को कम करने के लिए उस बयान पर बहुत विश्वास किया।

73% उत्तरदाता अनावश्यक छूट को कम करने के कथन से सहमत है या दृढ़ता से सहमत है।

केवल 19% करदाताओं का मानना है कि अनावश्यक छूट को कम नहीं किया जा सकता। बाकी उत्तरदाता अपने उत्तर में तटस्थ थे। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि नया कर कोड अनावश्यक छूट को कम करेगा।

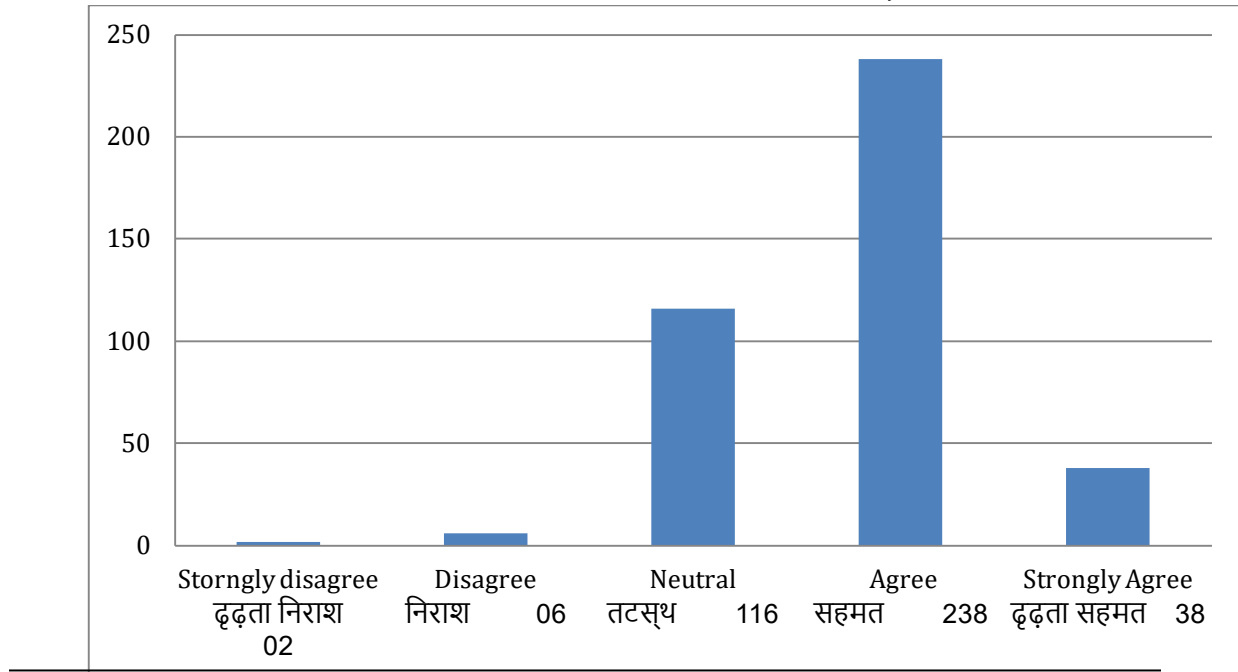
तालिका-4 (उद्देश्य 4)

ईईटी मॉडल भविष्य में अधिक कर एकत्र करेगा।

Opinion राय	frequency आवृत्ति	Percently प्रतिशत	Valid Percent वैध प्रतिशत	Cumulative Percent संचयी प्रतिशत
Strongly Disagree दृढ़ता निराश	2	0.5	0.5	0.5
Disagree निराश	6	1.5	1.5	2.0
Neutral तटस्थ	116	29.0	29.0	31.0
Agree सहमत	238	59.0	59.0	90.5
Strongly Agree दृढ़ता सहमत	38	9.5	9.5	100.0
Total कुल	400.0	100.00	100.00	-

(प्रश्नावली से संकलित)

ईईटी मॉडल भविष्य में अधिक कर एकत्र करेगा।



(प्रश्नावली से संकलित)

आकृति-04- ईईटी मॉडल भविष्य में अधिक कर एकत्र करेगा।

व्याख्या-

उपरोक्त तालिका 4 और आकृति 4 ईईटी मॉडल के बारे में उत्तरदाताओं की सहमति को दर्शाता है जो भविष्य में अधिक कर एकत्र करेगा, हम स्पष्ट रूप से दर्शा सकते हैं कि करदाताओं का बहुत विश्वास था कि ईईटी मॉडल भविष्य में अधिक कर एकत्र करेगा। लगभग 69% उत्तरदाता या तो इस कथन से सहमत है या दृढ़ता से सहमत है।

केवल 2% उत्तरदाताओं का मानना है कि ईईटी मॉडल भविष्य में अधिक कर एकत्र नहीं करेगा। साथ ही तटस्थ भी यह मानता है कि ईईटी मॉडल भविष्य में अधिक कर एकत्र करेगा।

प्रमुख निष्कर्ष:

अध्ययन से यह स्पष्ट है कि नई प्रत्यक्ष कर संहिता प्रणाली करदाताओं को कर सलाहकारों की सहायता के बिना आयकर रिटर्न की गणना करने में मदद करेगी। अध्ययन से यह स्पष्ट है कि नई प्रत्यक्ष कर संहिता प्रणाली करदाताओं को मध्यम राहत दिलाने में सहायक होगी। अधिकांश करदाताओं की राय है कि नई प्रत्यक्ष कर संहिता प्रणाली अनावश्यक छूटों को कम करेगी। अधिकांश करदाताओं की राय है कि नई प्रत्यक्ष कर संहिता भविष्य में ईईटी मॉडल द्वारा अधिक कर एकत्र करने में सहायक होगी।

सुझाव:

नई प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) करदाताओं को कर सलाहकार की सहायता के बिना आयकर रिटर्न की गणना और फाइल करने में सहायता कर सकती है, इसलिए यह जल्द ही नई कर संहिता प्रणाली को लागू करेगी।

नई प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) करदाताओं को मध्यम राहत दिलाने में सहायता करेगी, इसलिए इसे जल्द ही लागू किया जाएगा।

नई प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) अनावश्यक छूटों को कम करने में सहायता करेगी, इसलिए आयकर अधिनियम, 1961 को नई प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। नई प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) ईईटी मॉडल द्वारा भविष्य में अधिक कर एकत्र करने में मदद करेगी, इसलिए इसे जल्द ही पेश किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष:

परिणामों के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नई प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) करदाताओं को कर सलाहकार की मदद के बिना आयकर रिटर्न की गणना और फाइल करने में मदद कर सकती है।

अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि नई प्रत्यक्ष कर संहिता प्रणाली मूल्यांकनकर्ताओं को मध्यम राहत के लिए मदद करेगी। अध्ययन का निष्कर्ष है कि नई प्रत्यक्ष कर संहिता प्रणाली अनावश्यक छूट को कम करेगी।

अध्ययन के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नई प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) ईईटी मॉडल द्वारा भविष्य में अधिक कर एकत्र करने में मदद करेगी, इसलिए इसे जल्द ही पेश किया जाना चाहिए।

यह भारत सरकार के लिए डीटीसी के माध्यम से मौजूदा आयकर कानून को फिर से स्थापित करने के लिए एक प्रोत्साहन है, जो पांच दशक पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा, ताकि कानून को आसान बनाया जा सके, कर प्रणाली का प्रशासन हो सके, व्यापार करने का खर्च कम हो सके, विदेशी संसाधन और पूंजी आए और सुव्यवस्थित नियमों और विनियमों के साथ करदाताओं के लिए प्रणाली को अधिक कुशल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया जा सके। यह देश की आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार अधिनियम को संशोधित करने और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के विकास के साथ बने रहने का एक मौका है।

कोड किसी भी पूर्वाग्रह के साथ मौजूदा अधिनियम को बदलने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह कानून को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास और अवसर भी है, सरलता लाने के अलावा, कोड शुल्क भुगतान की पूर्वानुमेयता को आश्वस्त करेगा। नए कानून के प्रमुख सिद्धांतों में से एक सभी कर चोरी और परिहार का उन्मूलन था। कोड यथासंभव अस्पष्टता को प्रतिबंधित करता है, जिसे पहले विभिन्न विधायी और सरकारी स्तरों पर हल किया गया था। क्योंकि समय की मांग प्रत्यक्ष कर कानून के रूप में अधिक व्यापक कर सुधार है जो विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करता है, कॉर्पोरेट विश्वास को बढ़ावा देता है, ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करता है, अनुपालन

और प्रशासनिक बोझ को कम करता है, और एक पारदर्शी, स्थिर और कम मुकदमेबाजी वाला वातावरण प्रदान करता है। कर आधार में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए, यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था कर कानूनों का अधिक अनुपालन करे। इस तथ्य के बावजूद कि इसके घोषित उद्देश्य सराहनीय हैं, डीटीसी के मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण हैं। लेकिन हमेशा एक ही स्थिति के दो पहलू होते हैं।

भारत में प्रत्यक्ष कर संहिता आजकल बहुत चर्चा और आलोचना की जाती है। हालांकि डीटीसी के पीछे मूल उद्देश्य सरल और लोगों के लिए मददगार है, लेकिन इसकी बहुत आलोचना की जाती है क्योंकि इस प्रस्ताव के तहत कई प्रावधान निवेशकों और एफआईआई को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रत्यक्ष कर संहिता भारत की पूरी कराधान प्रणाली को बदलने के लिए तैयार है, क्योंकि कर प्रणाली कर चोरी को रोकने और कर के विस्तार को रोकने में विफल रही है। समानांतर अर्थव्यवस्था। 2012 में, भारत सरकार ने काले धन पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया कि समानांतर अर्थव्यवस्था भारत के सकल घरेलू उत्पाद के बराबर है। नए कानून के स्तंभों में से एक सभी कर चोरी और यहां तक कि कर से बचने का उन्मूलन है। जितना संभव हो सके, कोड अस्पष्टता को प्रतिबंधित करता है जिसे पहले विभिन्न विधायी और सरकारी स्तरों पर हल किया गया था। न्याय में देरी न्याय से इनकार है, इसलिए कोड एक फास्ट-ट्रैक निपटान विकसित कर रहा है। मूल्यांकन और प्रक्रियाओं को बाध्यता से मुक्त और तर्कसंगत बनाया गया है। कर प्रोत्साहनों को संकलित और समेकित करने के परिणामस्वरूप, लाभ उचित तरीके से दिए जाने चाहिए। कीमिया, 2013 का प्रत्यक्ष कर कोड, भारतीय वित्त के क्षेत्र में एक सुनहरा स्पर्श होगा। अंत में, डीटीसी के कार्यान्वयन में करदाताओं, कर अधिकारियों, कर सलाहकारों और न्यायालय सहित सभी पक्षों का समय और प्रयास लगेगा। इसके लिए मौजूदा कानून को भूलकर नए कोड को शुरू से सीखना होगा। सरकार को सभी आवश्यक पक्षों से परामर्श करने के बाद निष्पक्ष तरीके से इस परियोजना को आगे बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार, कुछ प्रावधान हैं जिन्हें 2023 में घोषित किए जाने वाले प्रस्तावित नए प्रत्यक्ष कर संहिता में शामिल किए जाने की उम्मीद है क्योंकि आदर्श कर मॉडल को प्रशासनिक सुधार, आर्थिक सुधार और कर नीति सुधार द्वारा एकीकृत और जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही, इससे भारत के विकास में वृद्धि होने की उम्मीद है क्योंकि कर में कमी उन्हें अर्थव्यवस्था के विकास में अपना पैसा योगदान करने के लिए प्रेरित कर सकती है, जैसे व्यावसायिक फर्म स्थापित करना, होटल बनाना आदि, जो अर्थव्यवस्था के विकास में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। लेकिन परिवर्तन होते हैं, जो सरकार की इच्छा को प्रदर्शित करते हैं कि उसे अपने जाल का विस्तार करना चाहिए और रिफंड और राहत के लिए कुछ लोकप्रिय अनुरोधों के जवाब में प्रतिक्रिया देनी चाहिए, विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए और कर चोरी और इस तरह की खामियों को दूर करना चाहिए। पेशेवरों, करदाताओं और सबसे पहले विषय के छात्रों को इनसे निपटना पड़ता है।

संदर्भ:

1. अंबिरंजन, एस. (1961)। भारत में कॉर्पोरेट आय का कराधान, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बॉम्बे, खंड 10, पृष्ठ 412-437 .
2. बर्ड, एम. रिचर्ड और एरिक एम. (2003)। “कर नीति डिजाइन और विकास का परिचय”, विकासशील देशों में कर नीति के व्यावहारिक मुद्दों पर एक पाठ्यक्रम के लिए तैयार मसौदा, विश्व बैंक।
3. बिश्रोई यू. (1980)। “भारत में संघीय कर”, चुघ प्रकाशन, इलाहाबाद, खंड 15, पृष्ठ 9-23 .
4. चेलिया, जे. (1992)। “कर सुधार समिति की अंतिम रिपोर्ट।”
5. डेविस, जी. (2011)। “संयुक्त राज्य अमेरिका के कर और कर नीति” कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, खंड 12, पृष्ठ 211-219 .
6. मिश्रा, बी. (2006)। कराधान का अर्थशास्त्र- सिद्धांत और अनुप्रयोग, आकांक्षा पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, खंड 5, पृष्ठ 78-92 .
7. वाधवा, एन. (2010). “प्रत्यक्ष कर संहिता सरलीकृत – डीटीसी के लिए संक्षिप्त और सरलीकृत मार्गदर्शिका”, नई दिल्ली टैक्समैन .
8. निशांत गेज, कटदारे , भारतीय कर संरचना और विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय जर्नल इन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस, खंड 3, अंक 9 .
9. आकांक्षा शर्मा, प्रत्यक्ष कर संहिता: खंड 1(2022) .
10. अरिंदम दास गुप्ता, राधिका लाहिनी, दिलीप मुखर्जी भारत में आयकर अनुपालन और अनुभवजन्य विश्लेषण विश्व विकास, खंड 23, अंक 12 पृष्ठ 2051-2064 .
11. 11.डा तरल कुमार पिनाकिन भाईभट्ट(2019)। आयकर अधिनियम 1961 पर नए प्रत्यक्ष कर कोड डीसी का प्रभाव खंड 6 अंक।
12. डॉ राकेश शाहा, भारत में प्रत्यक्ष कर संहिता का एक अवलोकन मानवता और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के अंतरराष्ट्रीय जर्नल।